सरकार से मिलों की मांग, चीनी का निर्यात कोटा बढ़ाएं

सरकार को इस बारे में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले करना होगा कोई फैसला

[जयश्री भोसले | पुणे]

जो चीनी मिलें एक्सपोर्ट कोटा का पूरा इस्तेमाल कर चुकी हैं, उन्होंने विदेश में और चीनी बेचने की इजाजत मांगी है। वे सरकार से इसकी पॉलिसी लाने को कह रही हैं। केंद्र को इस बारे में फैसला अगले महीने से चुनाव आचारसंहिता लागू होने से पहले करना होगा।

नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज (NFCSF) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो मिलें अपने एक्सपोर्ट कोटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहतीं, उसे उन मिलों को ट्रांसफर किया जाए तो इसका पूरा इस्तेमाल कर चुकी हैं।

इस पर NFCSF के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नायकनवरे ने कहा, 'ऐसी कई मिलें हैं, जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट कोटा पूरा कर लिया है। वे इससे ज्यादा शुगर एक्सपोर्ट करना चाहती हैं। मिलों को आवंटित कोटा के अतिरिक्त एक्सपोर्ट करने पर इंसेंटिव भी मिलना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'यदि चीनी मिलें अपने आवंटित कोटा को छोड़ना चाहें तो इसे उन्हें ट्रांसफर करना चाहिए जो तय कोटे से अधिक एक्सपोर्ट में दिलचस्पी रखती हैं।' NFCSF ने सरकार से मिलों को दो ग्रुप में बांटने की अपील की है। इसमें से एक वर्ग में ऐसी मिलों को रखा जाए, जो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं। दूसरे में उन मिलों को रखा जाए, जो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहतीं। सरकार ने 2018-19 में 50 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट का मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटा (एमआईईक्यू) तय किया था। मिलों ने अभी तक 18 लाख टन चीनी विदेशी बाजारों में बेचने का करार किया है। इसमें से 11 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है। शुरू में मिलें एक्सपोर्ट में रुचि नहीं दिखा रही थीं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू कीमतों के मुकाबले चीनी की कीमत कम थी। इंडस्ट्री के हालिया अनुमान के मुताबिक, करीब आधी मिलों ने आवंटित एक्सपोर्ट कोटा पूरा कर लिया है। फरवरी 2019 में क्रूड ऑयल के दाम नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे, जिससे चीनी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई थी।

- NFCSF ने कहा, जो मिलें चीनी का निर्यात नहीं करना चाहती हैं, उनका कोटा उन मिलों को ट्रांसफर किया जाए जिनकी शुगर एक्सपोर्ट में दिलचस्पी है

क्रूड ऑयल के दाम में इजाफा होने पर एथनॉल की वायबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे ब्राजील जैसे टॉप शुगर प्रोड्यूसर्स तुरंत ही चीनी का उत्पादन घटाकर एथनॉल का उत्पादन बढ़ा देंगे। नायकनवारे ने कहा, 'कच्ची चीनी के दामों में हालिया इजाफे से एक्सपोर्ट में संतुलन आया है। अगर सरकार पॉलिसी में बदलाव करके हमें ज्यादा एक्सपोर्ट की अनुमति देती है तो हम 25 लाख टन तक चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।'

मिलें या तो सीजन के शुरुआत में कच्ची चीनी का प्रॉडक्शन करती हैं या फिर सीजन के अंत में। दरअसल, उन्हें सफेद चीनी के प्रॉडक्शन की जगह कच्ची चीनी का प्रॉडक्शन करने के लिए मिल को एक दिन के लिए बंद करना पड़ता है। महाराष्ट्र की शुगर मिलों को कच्ची चीनी का प्रॉडक्शन करने के लिए और दो महीनों का वक्त मिलेगा क्योंकि गन्ने की कमी के चलते सीजन जल्द ही खत्म होने की संभावना है।

Economic Times

27/2/2019